eNEWS LETTER

Dec-2015

Jodhpur Development Authority was established under Jodhpur Development Authority Act,2009(Act No. 2 of 2009) under the Department of Urban Development and Housing, Government of Rajasthan for the purposes of planning, coordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of the Jodhpur Region and of executing plans, projects and schemes for such development and to provide for matters connected there with.

Composition of Jodhpur Development Authority

A Chairman appointed by the State Government

A Vice-chairman, Jodhpur Development Commissioner, Jodhpur

Principal Secretary to the Government, Urban Governance [Development and Housing] Department or his representative not below the rank of Deputy Secretary

Deputy Housing Commissioner, Rajasthan Housing Board, Jodhpur

Additional Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Jodhpur

Additional Chief Engineer, Public Works Department, Jodhpur

District Collector, Jodhpur

Chief Managing Director, Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd., Jodhpur

Chairman/Administrator, Municipal Corporation, Jodhpur

Zila Pramukh of Zila Parishad, Jodhpur

Deputy Town Planner, Jodhpur

Non official members, not exceeding seven to be nominated by the State Government

Contact us

Jodhpur Development Authority
Opposite Railway Hospital
Railway Hospital Road,
Ratanada, Jodhpur(Rajasthan) 342001 India
e-mail-jdajodhpur-rj[at]nic[dot]in
Phone No.- 0291-2612086, 0291-2656355
Fax No. - 0291-2615372

Ratan Lahoti
(I.A.S)
Chairman

"" जोधपुर शहर की जनता द्वारा किये गये अभिनन्दन के लिये आभार व्यक्त करता हूँ। शहर के समग्र विकास हेतु कार्य करना ही मेरा एक मात्र लक्ष्य हैं तथा इसी संकल्प के साथ मैं कार्य करूंगा।
जोधपुर शहर की जनता से अपील हैं कि शहर के विकास में अधिकाधिक भागीदारी निभाए ताकि शहर के विकास हेतु रचनात्मक एवं ठोस कार्य निरन्तर आगे बढे.। ""

Joga Ram
(I.A.S)
Commissioner

"" जोधपुर शहर के विकास में प्राधिकरण अपनी भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्पित है। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से जोधपुर के विकास में हम सब मिलकर अपना योगदान देंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ""

Durgesh Kumar Bissa
(R.A.S)
Secretary

"" जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर शहर के समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिए दृढ. संकल्प है। मेरा विश्वास है कि इस कार्य को सही दिशा में क्रियान्वित करने के लिए आप सबका अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा। आप हम सब मिलकर विकास के इस सपने को साकार करें। ""

Disclaimer

eNews Letter तैयार करने में सभी तथ्यों को सावधानी से चेक किया गया है। फिर भी मानवीय भूल से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे तथ्यों के आधार पर सुधार कर पुनः प्रदर्शित किया जा सकता है। आपके सुझाव व आपत्ति निम्न पते या ईमेल पर भिजवाए जा सकते है।

दिनांकः– 01/01/2016

पताः–जोधपुर विकास प्राधिकरण,
रेल्वे हॉस्पिटल के सामने, रेल्वे हॉस्पिटल रोड,
रातानाडा, जोधपुर।

ईमेलः– jdajodhpur-rj[at]nic[dot]in

फोनः– 97990–42144
देवेन्द्र गहलोत
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर

Concrete Activities

मुख्यमंत्री जन आवास योजना तनावड़ा व बड़ली में जेडीए बनाएगा 2800 फ्लैट्स –

जेडीए फ्लैट का आवंटन लॉटरी के आधार पर करेगा। इसके लिए 1200 रुपए स्क्वायर फीट रेट तय की गई है। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को कम से कम छह लाख रुपए में फ्लैट मिलेगा। ये फ्लैट वन बीएचके साइज का होगा। दोनों वर्ग में इसी टाइप के फ्लैट होंगे, लेकिन दोनों में साइज बढ़ जाएगी। कुल जमीन के क्षेत्र के 75 फीसदी एरिया में निर्माण होगा, जबकि 25 फीसदी में पार्क, रोड, स्कूल जैसी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी।

जेडीए ने इस योजना के लिए तनावड़ा के खसरा संख्या 136 में 5 एकड़ तथा बड़ली के खसरा संख्या 88 में 33 एकड़ जमीन चिह्नित की है। इनमें तनावड़ा में 400 तथा बड़ली में 2400 फ्लैट्स का निर्माण होगा। जेडीए ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 325 से 350 स्क्वायर फीट तथा अल्प आय वर्ग के लिए 500 से 550 स्क्वायर फीट साइज के फ्लैट का निर्माण होगा। इसके लिए प्री बिड मीटिंग 28 दिसंबर को होगी। इसके बाद 20 जनवरी को फाइनेंशियल बिड जारी होने के बाद फरवरी में काम शुरू होगा।

राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना लॉन्च की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर में जेडीए ने तनावड़ा बड़ली में साइट तय की है। दोनों ही स्थानों पर 2800 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाएगा। जेडीए इसके लिए कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर जी प्लस थ्री फ्लैट्स का निर्माण कराने जा रहा है। ये फ्लैट्स आर्थिक रूप से पिछड़े तथा अल्प आय वर्ग के लोगों को मिलेंगे। फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। जेडीए आयुक्त जोगाराम ने बताया कि इस योजना के लिए दोनों ही स्थानों पर 38 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इसकी बिड़ खुलने के बाद फरवरी तक इसका निर्माण शुरू होने की संभावना है।

शहर के मास्टर डेवलपमेंट प्लान में विजन बताएगी आईआईटी जोधपुर –

आईआईटी निदेशक ने जेडीए अफसरों के साथ बैठक में मौजूदा ड्राफ्ट प्लान को लेकर संशोधन पर की चर्चा
जोधपुर शहर के मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2031 के ड्राफ्ट को आईआईटी जोधपुर अपना विजन देना चाहती है। जोधपुर के भावी विकास की तस्वीर का खाका बताने वाले इस ड्राफ्ट में आईआईटी के विशेषज्ञ जेडीए को अपना विजन सुझाव देंगे। इसके लिए आईआईटी के निदेशक प्रो. सीवीआर मूर्ति तथा सलाहकार एमएल बाफना ने मंगलवार को जेडीए के अफसरों के साथ औपचारिक बैठक की। आईआईटी निदेशक ने जोधपुर का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए भी चर्चा की।

जेडीए में बैठक के दौरान आयुक्त जोगाराम, प्लानिंग विंग के अफसर तथा उपायुक्त मौजूद थे। प्रो. मूर्ति ने बताया कि आईआईटी जोधपुर के डेवलपमेंट को लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। इसके लिए डाटा एकत्रित किया जा रहा है। जोधपुर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके लिए भी सुझाव दिए जाएंगे।

Concrete Activities

इसके लिए आईआईटी मौजूदा मास्टर प्लान में विजन बताने में सहयोग करेगी। जोधपुर का विकास सेक्टर लेवल फैसिलिटी पर भी संभव है। इसके लिए मैप के आधार पर अलग–अलग क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं बताई जाएंगी।

जोधपुर विकास आयुक्त द्वारा जेडीए क्षेत्र की भूमियों व योजनाओं का सघन दौरा –

जोधपुर विकास आयुक्त जोगाराम द्वारा गुरूवार प्रातः 11 बजे से 3.30 बजे तक प्राधिकरण क्षेत्र की भूमियों व योजनाओं का सघन दौरा किया गया। दौरे के दौरान उनके साथ ज्ञानेश्वर व्यास निदेशक अभियांत्रिकी, मोहनसिंह राजपुरोहित उपायुक्त, भंवरलाल सुथार अधिशाषी अभियंता(सिविल), बी.एल.चौधरी अधिशाषी अभियंता(विद्युत), राजेश बोड़ा अधिशाषी अभियंता(पीएचई) एवं प्राधिकरण के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सर्वप्रथम आयुक्त द्वारा पिछली सरकार कार्यकाल के अन्तिम छः माह के दौरान संस्थाओं को आवंटित भूमियों मामले के संबंध में तत्कालीन सरकार के मंत्रीमण्डल द्वारा गांव गंगाणा के खसरा संख्या 2 व 3 के रकबा 23 बीघा भूमि अल–ईसाकिया, अल–असफाकिया को आवंटित की गई थी उक्त आवंटन को वर्तमान सरकार के मंत्रीमण्डल द्वारा विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए निरस्त किये जाने पर आयुक्त द्वारा उक्त खसरे की भूमि का निरीक्षण किया गया साथ ही अधिकारियों को वहां पर प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि संबंधी बोर्ड लगवाने के भी निर्देश प्रदान किये।

प्राधिकरण आयुक्त द्वारा ग्राम चौखा में अरिहन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग हेतु निर्मित किये जा रहे फ्लैट्स का मौका निरीक्षण कर कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश प्रदान किये। राजीव गांधी कोलोनी का दौरा करते हुए आयुक्त ने अभियंताओं को उक्त योजना में शेष रही सड़कों के निर्माण कार्य कराने के निर्देश प्रदान किये।

आयुक्त द्वारा रामराज नगर योजना का दौरा करते हुए संबंधित तहसीलदार को योजना में व्याप्त अतिक्रमणों की सूची बनाकर पेश करने के निर्देश दिये साथ ही अभियंताओं को उक्त योजना में बकाया सड़कों के निर्माण एवं विकास के निर्देश भी प्रदान किये।

प्राधिकरण आयुक्त ने दन्तोपंथ ठेगड़ी नगर योजना में भी व्याप्त अतिक्रमणों की सूची बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये। वाम्बे योजना का निरीक्षण करने के उपरान्त वाम्बे योजना हेतु जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल हेतु प्राधिकरण द्वारा राशि 50 लाख स्वीकृत कर संबंधित पीएचईडी अभियंता को तत्काल वाम्बे योजना में पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किये। वाम्बे योजना के आस–पास व्याप्त अतिक्रमणों से असंतोष जाहिर करते हुए उक्त अतिक्रमणों की भी सूची बनाने के निर्देश प्रदान किये गये।

Concrete Activities

अखेराजजी का तालाब के आस–पास का मौका निरीक्षण करते हुए तालाब के आस–पास अवैध अतिक्रमणों की भी सूची बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश आयुक्त द्वारा प्रदान किये गये।

आयुक्त द्वारा अरणा विहार योजना, बड़ली का निरीक्षण किया गया। योजना में चल रहे मुटाम निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संतोष जाहिर किया तथा साथ ही अभियंताओं को शीघ्र ही सड़कों, नाला व मुख्य द्वार निर्माण हेतु निर्देश प्रदान किये।

सम्पर्क समाधान व लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों का होगा शीघ्र निस्तारण –

जोधपुर विकास आयुक्त जोगाराम द्वारा मंगलवार प्रातः 12 बजे अपने कक्ष में प्राधिकरण अधिकारियों की सम्पर्क समाधान व लोक सेवा गारंटी के लम्बित प्रकरणों की समीक्षात्मक बैठक ली। बैठक में प्राधिकरण सचिव दुर्गेश बिस्सा, उपायुक्त मोहनसिंह राजपुरोहित व राजेन्द्रसिंह राठौड़, निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक विधि, निदेशक आयोजना, निदेशक वित्त, देवेन्द्र गहलोत एसीपी, समस्त अधिशाषी अभियंता, तहसीलदार व विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में बकाया प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आयुक्त जोगाराम ने बारी–बारी से प्रकरणों में देरी के कारणों के बारे में जानकारी लेते हुए अधिकारी गणों को निर्देश प्रदान किये कि दैनिक कार्यों के साथ–साथ लोक सेवा गारंटी, सम्पर्क समाधान, सुगम–समाधान, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार आदि प्रकरणों का भी साथ–साथ यथा समय निस्तारण किया जाये ताकि प्राधिकरण की छवि और भी सुदृढ हो। साथ ही आयुक्त ने समयावधि पार प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश भी प्रदान किये। आयुक्त महोदय ने वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नवीन ऑनलाइन फाइल ट्रेकिंग सिस्टम का भी समुचित उपयोग करने के निर्देश दिये। जोधपुर विकास आयुक्त ने सभी शाखा प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किये कि समस्त अधिकारी व कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित रहे।

प्राधिकरण सचिव ने ली बैठक –

जोधपुर विकास प्राधिकरण सचिव दुर्गेश बिस्सा ने अपने कक्ष में समीक्षात्मक बैठक ली। बैठक में उपायुक्त मोहनसिंह राजपुरोहित व राजेन्द्रसिंह राठौड़, निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक विधि, निदेशक आयोजना, निदेशक वित्त, समस्त अधिशाषी अभियंता, विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में बकाया प्रकरणों की समीक्षा करते सचिव ने अधिकारी गणों को लोक सेवा गारंटी, सम्पर्क समाधान, सुगम–समाधान, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार आदि प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में अपने सुझाव व अनुभव भी साझा किये।

Concrete Activities

बिस्सा ने राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त प्रकरणों/शिकायतों तथा आमजन की समस्याओं की सुनवाई उनके त्वरित समाधान व निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग राजस्थान सरकार से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जिला कलक्टर द्वारा पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि उक्त प्रांसगिक परिपत्र अनुसार कार्यवाही करें साथ ही राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज शिकायतों में प्रार्थी को पत्र जारी कर सूचना भी देवें । बिस्सा ने अधिकारियों से कहा की आगामी सोमवार तक अवधि पार प्रकरणों की पेंडेन्सी शून्य पर रखें।

टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु कमेठी का गठन –

जोधपुर विकास प्राधिकरण सचिव दुर्गेश बिस्सा ने राज्य सरकार के परिपत्र के आदेशानुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए अनुज्ञा एवं भूमि के आवंटन नियम, 2012 व टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु जोनवार कमेटियों का गठन किया है । प्राधिकरण सचिव बिस्सा ने बताया कि सम्बन्धित जोन अधिशाषी अभियन्ता, तहसीलदार व सहायक नगर नियोजक द्वारा टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुरुप आन्तरिक विकास कार्यो की स्थिति की जॉच कर रिपोर्ट सम्बन्धित जोन के उपायुक्त के माध्यम से प्रस्तुत करेगें।

प्राधिकरण सचिव बिस्सा ने बताया कि निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा योजना का प्लान अनुमोदन करवाने के दौरान आन्तरिक विकास कार्य हेतु 12.5 प्रतिशत भूखण्ड़ रहन के रुप टाउनशिप पॉलिसी 2010 के नियमानुसार में रखे जाते है जिसका नवीन परिपत्र दिनांक 5.11.15 के अनुसार मॉरगेज–डीड प्राधिकरण के हक में निष्पादित किया जाना आवश्यक है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि आन्तरिक विकास कार्य हेतु निर्धारित समयावधि 2 हैक्टयर तक की योजनाओं में 18 माह निर्धारित है। बिस्सा ने बताया कि 2 से 10 हैक्टयर तक की योजनाओं के लिए 36 माह तक एवं 10 हैक्टयर से अधिक के लिए टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना होगा।

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि आन्तरिक विकास कार्य यथा सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाईट, जलापूर्ति, सीवरेज व ड्रेनेज, वृक्षारोपण के कार्यो हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये है। बिस्सा ने बताया कि टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर ही इन्हें रहन मुक्त किये जाने का प्रावधान है ।
बिस्सा ने कहा कि आमजन को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्राधिकरण क्षेत्र में ले–आउट प्लान अनुमोदित किये बिना अवैध रुप से यदि प्लॉट बनाकर बेचे जाते है तो ऐसे कृषि भूमि पर काटे गये आवासीय भूखण्ड क्रय न करें। प्राधिकरण की योजनाओं अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजनाओं में ही भूखण्ड़ का क्रय करें ।

Concrete Activities

प्राधिकरण सचिव ने ली बैठक –

जोधपुर विकास प्राधिकरण सचिव दुर्गेश बिस्सा ने आज अपने कक्ष में समीक्षात्मक बैठक ली। बैठक में उपायुक्त मोहनसिंह राजपुरोहित व राजेन्द्रसिंह राठौड़, निदेशक विधि, निदेशक आयोजना अतुल बल रतनू, अतिरिक्त निदेशक(वित्त), समस्त अधिशाषी अभियंता, विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारी मौजूद थे।
सर्वप्रथम बैठक में प्राधिकरण द्वारा अब तक ली गई बैठकों यथा कार्यकारी समिति, ले–आउट प्लान समिति, भवन निर्माण अनुज्ञा समिति की बैठकों में प्रदत्त निर्देशों व निर्णय का प्रकरणवार समीक्षा प्राधिकरण सचिव द्वारा की गई। बिस्सा ने बताया कि अधिकांश प्रकरणों में अधिकारीगण द्वारा निर्णयों की पालना की जा चूकी है, कुछ प्रकरणों में आवेदकों को निर्धारित प्रारुप में आवेदन करने हेतु सूचित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया।

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि सम्पर्क/समाधान, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, सूचना के अधिकार व लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त पत्रों के निस्तारण कर राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज शिकायतों में प्रार्थी को पत्र जारी कर सूचना भी देवें ।

प्राधिकरण सचिव ने योजना शाखा को निर्देशित किया गया है कि जल्द ही ले–आउट कमेटी की नवीन बैठक व बिल्ड़िग प्लान कमेटी की बैठक आयोजित करे साथ ही पूर्व में आयोजित बैठक में स्वीकृत सभी प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण करें। बिस्सा ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आर्थिक रुप से कमजोर आयवर्ग व अल्प आय वर्ग हेतु प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही योजनाऐं लॉच की जायेगी। बिस्सा ने विभिन्न योजनाओं में चल रहे विकास कार्यो का ब्यौरा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये की सभी प्रकार से विकास कार्य में उच्च गुणवता व मापदण्ड़ो का पुरा ख्याल रखा जावे।

प्राधिकरण सचिव ने लेखा शाखा से विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाली आय व व्यय के बारे में ब्यौरा लेते हुए सन्तोष व्यक्त किया साथ ही विभिन्न विभागों हाउसिंग बोर्ड व रिको इत्यादि विभागों से बकाया हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से बैठक कर वसुली में तेजी लाने के निर्देश भी प्रदान किया।

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि बैठक में प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालयों में लम्बित प्रकरण की समीक्षा करने पर पाया गया अधिकतर प्रकरण नगर निगम से सम्बन्धित है, जिस पर सचिव ने न्यायालय को इस आशय का शपथ–पत्र देने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने के निर्देश किये की सम्बन्धित प्रकरणों की पत्रावलियां यदि निगम को नहीं भिजवाई गई है तो वे पत्रावलियां भी विधिक पत्रावलियों के साथ भिजवाये जाने की व्यवस्था करावें।

प्राधिकरण सचिव दुर्गेश कुमार बिस्सा ने बताया कि बैठक के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं व जानकारी जोधपुर विकास आयुक्त को ब्रीफ कर दी गई है।

Concrete Activities

नगरीय विकास मंत्री ने ली बैठक –

जोधपुर विकास प्राधिकरण सचिव दुर्गेश बिस्सा ने बताया कि नगरीय विकास मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने रविवार को सर्किट हाउस में जेडीए के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्राधिकरण आयुक्त जोगाराम, सांसद श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत प्राधिकरण के समस्त उपायुक्त, प्राधिकरण निदेशक के साथ–साथ प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद थे। मीटिंग के उपरान्त राज्यसभा सांसद श्री नारायण पंचारिया, व सूरसागर विधायक श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास भी उपस्थित रहे।

बिस्सा ने बताया कि आयुक्त द्वारा नगरीय विकास मंत्री को प्राधिकरण की वर्तमान वितीय स्थिति व आय बढ़ाने हेतु प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयास, नवीन योजनाओं से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय, भावी नवीन योजनाओं, जोधपुर रीजन के मास्टर डवलपमेंट प्लान(प्रारूप) 2031, अधिकारी व कर्मचारी के रिक्त पद, शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यो यथा निर्माणाधीन/निर्मित आरयूबी एवं आरओबी, सीवरेज परियोजना, पेयजल परियोजनाएं व प्राधिकरण द्वारा करवाये जा रहे विकास कार्यो एवं प्राधिकरण द्वारा वितीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियों की जानकारी, प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं व उनमें किये जा चूके व किये जा रहे विकास कार्य, जोनवार प्रगतिरत कार्यो का विवरण, जोधपुर शहर की मुख्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण व सौन्दर्यकरण का कार्य, बजट घोषणा 2014–15 में दिये गये मुख्यमंत्री निर्देश के बिन्दुओं की क्रियान्विति, सुराज संकल्प 2013 तथा मुख्यमंत्री निर्देश संबंधी अद्यतन सूचना, कॉम्प्रीहैंसिव मोबिलिटि प्लान, अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी, लैण्ड बैंक, एकल खिडकी, सुगम पोर्टल, ई–पोर्टल व सूचना प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न कार्य यथा वेबसाईट, ई–पोर्टल, ई–टेण्डर, ई–ऑक्शन, बजट प्रावधानों के अनुरूप की गई प्राप्तियां व व्यय के बारे में जानकारी देते हुए राज्य स्तर पर बकाया चल विविध बिन्दुओं व सरकार के उचित विधिक मार्गदर्शन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि आयुक्त द्वारा नगरीय विकास मंत्री को बैठक में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा जीआईएस सिस्टम के तहत लैण्ड बैंक बनाकर नेट पर डालने की कार्यवाही करने के संबंध में रिर्मोट सेंन्टर को कार्यादेश दिया जा चुका है तथा जीआईएस सिस्टम के तहत लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही प्राधिकरण द्वारा नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति, भू–आवंटन, उप विभाजन, पुनर्गठन प्रॉपटी रजिस्टर, लीज गणना, लीज बकायादारों की सूचना, भवन निर्माण अनुज्ञा, मासिक प्रगति रिर्पोट व इंजीनियरिंग मैनजमेंट सिस्टम की प्रक्रिया ऑन लाईन करने का कार्य प्रगति पर है।

नगरीय विकास मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये की समस्त विकास कार्य समयबद्धता व गुणवता के साथ पुरे किये जाये, उन्होनें वर्तमान में चल रहे आरओबी सहित विभिन्न विकास कार्यो में गहरी रुचि दिखाते हुए समय पर गुणवता के साथ पुरा करने के निर्देश भी प्रदान किये।

Concrete Activities

शेखावत ने अधिकारियों से मास्टर प्लान 2031 को यथाशीघ्र लागु करने के निर्देश भी प्रदान किये। शेखावत ने अधिकारीगण से बिल्डिंग प्लान समिति, ले–आउट अनुमोदित करने आदि की बैठक शीघ्र कर बकाया प्रकरणों के निस्तारण पर जोर दिया। शेखावत ने कहा इससे प्राधिकरण की आय बढ़ने के साथ–साथ आमजन को राहत मिलेगी। नगरीय विकास मंत्री ने शहर के सड़क, पेयजल, यातायात, सिवरेज, अतिक्रमण, नवीन योजनाओं, आय बढ़ाने के स्त्रोतों, रिंग रोड़, मुख्यमंत्री आवास योजना, अर्फोडेबल हाउसिंग, गारन्टी पिरियड के अन्तर्गत मरम्मत योग्य सड़कों, आमजन से अधिकारियों से मिलने की सुविधा सहित विभिन्न प्रश्न अधिकरियों से पूछे जिसका प्राधिकरण आयुक्त व सचिव द्वारा जवाब दिये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए उचित निर्देश भी प्रदान किये गये।

प्राधिकरण की नवीन आवासीय योजना अरणा विहार में आवेदकों का भारी उत्साह –

प्राधिकरण के उपायुक्त मोहनसिंह राजपुरोहित ने बताया कि आवेदन पत्र इंडसइंड बैंक के जोधपुर की सभी शाखाओं के माध्यम से 28 दिसम्बर तक प्राप्त किये जा सकेगे। आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि 7 जनवरी 2016 निर्धारित की गई है। इंडसइंड बैंक के अधिकारी ने अवगत कराया है कि भरे हुए आवेदन–पत्र के साथ यदि आवेदक केन्शिल चैक नहीं लगा पाता है तो चैक अथवा चैक बुक की फोटो कॉपी भी लगा सकते है जिसमें की आवेदक के बैंक के आईएफएससी कोड व शाखा के कोड अंकित हो ।

प्राधिकरण के उपायुक्त ने बताया कि प्राधिकरण की अरणा विहार आवासीय योजना में भूखण्डों का आकार 40.5 वर्गमीटर, 72 वर्गमीटर, 120 वर्गमीटर, 162 वर्गमीटर, 234 वर्गमीटर, 375 वर्गमीटर तक के भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित किये जायेगे योजना की आरक्षित दर रू. 5800 प्रति वर्गमीटर रखी गई है। इस योजना में कुल भूखण्डों की संख्या 943 है। योजना में नियमानुसार सरकारी कर्मचारियों, सैनिक/सेवा निवृत सैनिक एवं सेवाकाल के दौरान वीरगति को प्राप्त सैनिकों विधवायें, एवं आश्रित, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, निःशक्त जन, अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिये आरक्षण रखा गया है। राजपुरोहित ने बताया कि विभिन्न आयवर्ग अनुसार वसूली योग्य आरक्षित मूल्य में जिनका वेतन 10 हजार रूपये से अधिक नही है उनको आरक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत राशि पर भूखण्ड आवंटित किया जायेगा। इसी प्रकार जिनकी आय 10 हजार एक से 15 हजार रूपये तक है उनको आरक्षित मूल्य के 60 प्रतिशत पर भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित किया जायेगा ।

प्राधिकरण की आय बढ़ाने के लिए विशेष अभियान –

प्राधिकरण निदेशक वित्त आरपी शर्मा ने बताया कि आयुक्त के निर्देशानुसार प्राधिकरण निरन्तर अपनी आय बढाने के लिए प्रयासरत्त है। शर्मा ने बताया की प्राधिकरण द्वारा हॉल ही है तीन नवीन योजनाओं की लांचिग की गई है साथ ही दो योजनाओं में सफल आवंटियों को आवंटन पत्र भी जारी किये जा चुके है। प्राधिकरण निदेशक अभियान्त्रिकी ने बताया कि नवीन योजनाओं में मुटाम लगाने का कार्य किया जा चुका है। आवंटियों द्वारा राशि जमा कराने पर उनको हाथों–हाथ भूखण्ड का कब्जा प्रदान करने के निर्देश सम्बन्धित अभियंता को प्रदान किये गये है।

Concrete Activities

प्राधिकरण एसीपी देवेन्द्र गहलोत ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अपने भूखण्ड का स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति की सूचना व बकाया लीज की सूचना अब प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। प्रायः देखा गया है कि प्राधिकरण में व्यक्ति अपने भूखण्ड की लीज राशि जमा कराने हेतु चक्कर लगाता रहता है इस प्रकिया से आवंटियों को समय पर बकाया लीज राशि की जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट पर मिल सकेगी जिससे उन्हे अनावश्यक रूप से शास्ति व ब्याज राशि से राहत मिलेगी साथ ही प्राधिकरण को यथा समय बकाया राशि प्राप्त हो सकेगी। प्राधिकरण में चल रहें कम्प्यूटराईजेशन में लीज डिफाल्टर व प्रोपर्टी रजिस्ट्रर की ऑन लाईन सूची विभाग की वेबसाईट www.jodhpurjda.org पर दर्शायी गयी है। इसमें सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर लगभग 12 आवासीय योजना के भूखण्डों की लीज राशि वेबसाईट पर उपलब्ध साफ्टवेयर द्वारा गणना कर बकाया राशि जमा करवाई जा सकती हैं तथा इन्हे विभाग की वेवसाईट से डाउनलोड़ किया जा सकता है, इसे विभाग के सिंगल विन्डों से भी स्वयं जाकर बकाया लीज राशि का गणना प्राप्त कर सकते है। विपत्र पत्र में दर्शायी गयी राशि को चालान द्वारा एकल खिड़की पर जमा किया जा सकता है।

इसी तरह से प्रोपर्टी रजिस्टर से व्यक्ति प्लॉट एरिया, प्लॉट के स्वामित्व, प्लॉट नम्बर व सेक्टर देखे जा सकते है। यह लिंक वेवसाईट के मुख्य पृष्ठ पर स्किम व अलोटी पर क्लिक कर देखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को इसमें किसी प्रकार की भिन्नता मिलती हैं तो विभाग में आकर इसे दुरूस्त करवाया जा सकता है।जल्द ही सभी योजनाओं के भू–आवंटियों के नाम व बकाया लीज राशि को ऑन लाईन देखी जा सकेगी।

प्राधिकरण निदेशक वित्त आरपी शर्मा ने बताया कि प्राधिकरण में विभिन्न लीजडीड धारकों की करोड़ो रुपये की लीज राशि बकाया चल रही है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने बकाया लीज राशि की वसूली में गति जाने के लिए विशेष दलों का भी गठन किया है। जेडीए आयुक्त के निर्देशानुसार जेडीए की बकाया लीज राशि वसूलने के लिए अभियान चलाकर कार्य किया जाऐगा। जेडीए आयुक्त जोगाराम के आदेशानुसार पूर्व जोन में जेडीए के सहायक लेखाधिकारी द्वितीय प्रेम प्रकाश जोशी, कनिष्ठ अभियंता कानाराम और संबंधित जोन के लिपिक अशोक गिरि होगें। इसी प्रकार पश्चिम जोन में सहायक लेखाधिकारी केके चौहान, कनिष्ठ अभियंता प्रशांत पुरोहित और संबंधित जोन के आवंटन शाखा के लिपिक होगें।इसी तरह दक्षिण जोन में सहायक लेखाधिकारी द्वितीय गणपतलाल प्रजापत, कनिष्ट अभियंता विष्णुदत्त व्यास व सम्बन्धित जोन के आवंटन शाखा का लिपिक, उत्तर जोन के सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कन्हैयालाल सुखवानी, कनिष्ठ अभियंता मोहम्मद अफाक और संबंधित जोन के आवंटन शाखा के लिपिक होगें।

जेडीए आयुक्त ने बताया कि चारों जोन की टीमों में प्रर्वतन निरीक्षकों को भी शामिल किया जाऐगा। सभी जोन के समन्वयक अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट, अतिरिक्त निदेशक(वित्त) को प्रस्तुत करेगें तथा अतिरिक्त निदेशक(वित्त) बकाया लीज वसूली का शत प्रतिशत वसूली हेतु दिन प्रतिदिन मोनीटरिंग करेगें तथा सप्ताह के मगंलवार को निदेशक वित्त के कक्ष में सभी दलों के साथ उपस्थित होकर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगें।

Concrete Activities

प्राधिकरण निदेशक वित्त ने बताया कि प्रत्येक बुधवार निदेशक(वित्त), अतिरिक्त निदेशक(वित्त) व संबंधित उपायुक्त एवं सभी बकाया लीज वसूली दल के साथ आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण के कक्ष में उपस्थित होकर प्रगति की समीक्षा करेगें।

प्राधिकरण ने किया लिंक अधिकारियों का गठन –

जोधपुर विकास प्राधिकरण निदेशक अभियान्त्रिकी ने बताया कि आयुक्त के निर्देशानुसार प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्तागण के आकस्मिक या अन्य अवकाश व राजकीय कार्यवश जोधपुर से बाहर होने की स्थिति में लिंक अधिकारी द्वारा सामान्य व रुटिन की पत्रावलियों का निस्तारण किया जायेगा ।

निदेशक ने बताया कि अधिशाषी अभियन्ता –पूर्व के लिंक अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता–उत्तर इसी प्रकार पश्चिम का अधिशाषी अभियन्ता दक्षिण रहेगें। अधिशाषी अभियन्ता उत्तर के पूर्व व दक्षिण के पश्चिम रहेगें।निदेशक ने बताया कि अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालय के अधिशाषी अभियन्ता–गुण नियंत्रक खण्ड व गुण नियंत्रक खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता के अवकाश पर रहने पर उनका कार्य अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालय देखेगें।

इसी प्रकार अधिशाषी अभियन्ता आरओबी के अवकाश पर रहने पर अधिशाषी अभियन्ता पीएचई कार्य का निस्तारण करेगें। अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत(जोन पश्चिम/दक्षिण) का कार्य अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत(जोन–पूर्व/उत्तर) देखेगें। इसी प्रकार अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत (जोन–पूर्व/उत्तर) का कार्य अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत(जोन पश्चिम/दक्षिण) देखेगें। बिस्सा ने बताया कि इस प्रकार आमजन व कार्यालय का कार्य बाधित नहीं होगा व कार्य को नई गति व दिशा मिलेगी।

सर्किट हाउस से एयरपोर्ट रोड को नया लुक देने का कार्य शुरू –

सर्किट हाउस से एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सड़क को नया लुक देने के लिए जेडीए ने काम शुरू कर दिया है। ये काम तीन चरणों में होगा। पहले चरण में सर्किट हाउस से भाटी चौराहे तक सवा किमी तक रोड बनाई जाएगी। फिर इतनी ही दूरी तक भाटी चौराहे से पांच बत्ती सर्किल तथा वहां से अफसर मेस होते हुए एयरपोर्ट तक पूरी रोड को गौरव पथ से राजपथ में तब्दील करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जेडीए ने सर्किट हाउस से काम शुरू कर दिया है। सर्किट हाउस के गेट के साइड की दीवार तोड़ी गई है। रोड के दोनों ओर फुटपाथ पार्किंग बनाने का काम होगा। जेडीए आयुक्त जोगाराम ने बताया कि जेडीए ने काम शुरू करवा दिया है। पहले रोड को संवारने के बाद इस पर प्रतिकृतियां लगाई जाएंगी।

जेडीए ने राजपथ बनाने के लिए प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। पहले चरण में 38 लाख की लागत से रोड के दोनों ओर फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, पार्किंग और ड्रेनेज को सुधारा जा रहा है। मुख्य कार्य के लिए साढ़े तीन करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। इसका काम दूसरे चरण होगा।

Concrete Activities

राजपथ जैसी रोड बनाने के लिए करीब सवा दो किमी लंबी सड़क पर मुख्य रूप से दो स्थानों पर स्तंभ लगेंगे। सर्किट हाउस के मुख्य गेट के साथ ही एक और गेट बनेगा। पहले यहां अशोक स्तंभ बब्बर शेर के प्रतीक लगाए जाने थे। अशोक स्तंभ का उपयोग सेरेमोनियल तौर पर होता है। इसके चलते अब कलात्मक खंभे लगाने का प्रस्ताव है। इस पूरी डिजाइन पर सीएमओ से बात चल रही है। सीएमओ को निजी आर्किटेक्ट की ओर से तैयार की डिजाइन भेजी गई थी। इसके तहत भाटी चौराहे के अंदर साठ फीट लंबा राजस्थानी शैली में ऊंट हाथी का शाही कारवां बनाया जाएगा। भाटी चौराहे के चारों ओर तथा इसे जोड़ने वाली चार सड़कों पर 50–50 मीटर के कर्व स्टोन लगेंगे। रोड के दोनों ओर पार्किंग हरियाली विकसित होगी। इसकी सिंचाई का सिस्टम भी बनाया जाएगा।

Concrete Activities

Concrete Activities